

बिहार की लोकतांत्रिक राजनीति में अशराफ बनाम पसमांदा मुसलमानों की राजनितिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा

Research Scholar : Mojahedul Islam
University Department of Political Science,
B.R.A.Bihar University, Muzaffarpur

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष "काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी" फरमाते हैं – परन्तु हमें इस सच्चाई की अनदेखी नहीं करनी चाहिए की सही अर्थों में जाति प्रथा के नहीं रहते हुए भी जाति जैसे पूर्वाग्रह का अस्तित्व हमारे अंदर है।

यदि हम 1901 की जनगणना रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो उस रिपोर्ट के अनुसार 133 जातियों की पहचान की गयी थी, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से मुसलमान थे। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुस्लिम समाज मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त है।

अशराफ, अजलाफ तथा अरजाल। पहले में कुलीन तथा उच्च परिवार के लोग आते हैं। इसमें भी दो भाग हैं। पहला वे जो विदेशी मूल के हैं, मतलब जो अरब, पर्शिया, तुर्की अथवा अफगानिस्तान से यहां आकर बस गये हैं। दूसरे वे सवर्ण हिन्दू जो धर्म बदल कर मुसलमान बन गये। अजलाफ में हिन्दूओं की नीची जाति से धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बने लोग आते हैं। मुसलमानों की तीसरी श्रेणी के बारे में 1901 की जनगणना रिपोर्ट कहती है—कुछ स्थानों पर तीसरा वर्ग भी है जो अरजाल अथवा नीची जातियों में भी सब से नीचे आते हैं। इनमें हलाल खोर, लाल बेगी, अबदाल, और बेदिया आदि शामिल हैं।

बिहार में पिछड़े और दलित मुसलमानों को लेकर राजनीति करवट ले रही थी। यह लड़ाई अगड़े मुस्लिम समुदायों द्वारा की जा रही है। कमरिया के खिलाफ केन्द्रित थी। शिक्षा दीक्षा में पीछे और हाशिये पर पड़े दलित व सतयेहुए मुसलमानों के बारे में सुगबुगाहटें तेज हुईं तो पसमांदा और पिछड़े हुए मुसलमानों के संगठनों पर ही सवाल उठने शुरू हो गये। पसमांदा मुसलमानों ने जब कहा कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है, तो कहा जाने लगा की यह मुसलमानों की एकता में फूट डालने की कार्रवाई है।

बिहार में मुसलमानों का अशराफ बनाम अजलाफ का प्रतिनिधित्व करतारहा है। सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह है की मंडलवादी राजनीति के नेतृत्वकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रासाद यादव एवं वर्तमान नितीश कुमार के विगत 30 वर्षों के शासनकाल के सामाजिक न्याय के दौर में भी पिछड़े मुसलमानों को न्याय नहीं मिला है। नितीश कुमार की कैबिनेट में भी दो मुसलमान मंत्री बनाये गए – प्रवीण अमानुल्लाह और शाहिद अली खान जो कि अगड़े जाति से आते हैं, अलबत्ता सन् 1983-1985 में के कांग्रेस के शासनकाल में चंद्रशेखर सिंह के मुख्यमंत्री काल के दौरान पसमांदा मुसलमानों को अति पिछड़ों में शामिल किया गया था। यदि 1952-2000 तक के विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो कुल 275 मुसलमान

उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीते, जिसमें 215 केवल अगड़े जाति के थे एवं वहीं पिछड़े जाति से मात्र 58 मुसलमान विधानसभा चुनाव जीते, जबकि इनका कुल प्रतिशत 85 मानी जाती है, जो कि अपने आप में कहीं से न्यायोचित नहीं है स उसी प्रकार यदि 1952-2009 लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो कुल 54 मुसलमान लोकसभा पहुंचे थे, जिसमें पिछड़ों कि संख्या केवल 14 थी इससे साफ जाहिर होता है की अगड़े एवं पिछड़े मुसलमानों में हमेशा से ही गैर बराबरी रहा है जोकि कतई संतोषजनक नहीं है ।

शिक्षाकाक्षेत्रहोअथवाराजनीतियाजमीन,सभीमामलेमेंअशराफसमुदायहीआगेरहाहै।पिछड़ेपसमांदामुस्लिमसमुदाययाहिन्दूपिछड़ोंकेत्रिवेणीसंघकीतरहकोईसंगठनने कारगरपहलकदमी नहींकी।

अब्दुलकययूमअंसारीने40केदशकमेंमोमिनतहरीककेजरियेऐसीकोशिशकीथीजिसनेअपनीएकस्वतंत्रपहचान बनायी,परआजादीकेबादउसेएकसिलसिलानहींदियाजासका।मोमिनराजनीतिकेझण्डाबरदारपार्टियोंऔरगुटोंमेंबंदकर राजनीतिकरतेरहे।उपरसेदेखनेसेलगताहैकीमुसलमानोंमेंउंचनीचअथवागैरबराबरीकाभेदनहींहै,लेकिनवास्तविकताइससेअलगहै।वहीं मुसलमानों की कुल आबादी का सवर्ण मुसलमान मात्र15फीसद हैं और दलित, पिछड़े और आदिवासी मुसलमान85फीसद होते हैं 1990के दशक में बिहार से डॉ. एजाजअलीके 'ऑलइण्डियाबैकवर्डमुस्लिम मोर्चा', अली अनवर के 'ऑलइण्डियापसमांदामुस्लिममहाज' औरमहाराष्ट्रसे शब्बीरअंसारीके 'ऑलइण्डियामुस्लिमओबीसीआर्गनाइजेशन' एवंअलीअनवरकीकिताब"मसावातकीजंग"औरसाथहीमसूदआलमफलाहीकी"हिन्दुस्तानमेंजातपातऔरमुसलमान"जैसेपुस्तकों एवं संगठनों ने मुसलमानों के भीतर जाति विनाश के सामाजिक आंदोलनों को नयी गति दीहै।वहीं कांशीराम ने मुस्लिम समाज के अपने अनुभव के बारे में एक बार कहा थारू 'मुसलमानों में मैंने नेतृत्व के स्तर से जाना ठीक समझा, उनके पचासों नेताओं से मैं मिला। इनमें भी ब्राह्मणवाद देखकर मैं दंग रह गया। इस्लाम तो बराबरी और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाता है, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व शेख, सय्यद, मुगल, पठान यानि अपने को ऊंची जाती के मानने वाले लोगों के हाथ में है, वह यह नहीं चाहते कि अंसारी, धुनिया, कुरैशी उनकी बराबरी में आये....। मैंने फैसला किया की मुसलमानों में हिंदुओं की अनुसूचित जातियों से गए लोगों को ही तैयार किया जाए।' (सतनाम सिंह, कांशीराम की नेक कमाई जिसने सोती कौम जगाई, सम्यक प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2007, पेज. 132)

सच यह भी है की जातिगत भेद भाव के साथ शिक्षा और आर्थिक मामले में भी मुसलमानों का यहसमुदायहाशियेपरहै।2001कीजनगणनाकेअनुसारमुसलमानोंमेंसाक्षरतादर42प्रतिशतहै।महिलासाक्षरतादर31.5प्रतिशतहै।बहरहाल,एकजमानेमेंजनगणनामेंअपनानाममोमिनकेस्थानपरशेखमोमिनलिखवानेकासिलसिलाशुरूहुआथा।हालकेवर्षोंमेंऊंचीजातिकेमुसलमानोंमेंमल्लिकऔरशेखसमुदायोंकेलोगोंनेअपनानामअतिपिछड़ोंमेंदर्जकरानेकेलिएआवेदनदियाथा।यहसबपरिस्थितियोंकीमारथी।आरक्षणकेदायरेसेयेसमुदायबाहरथे।उन्हेंलगाकिऐसाकरनेसेआरक्षणकाफायदामिलसकताहै।दलितऔरपिछड़ेमुसलमानोंनेइसबातकोजबजानातोउसकाजमकरविरोधकिया।पिछड़ावर्ग आयोगनेभीइनआवेदनोंकोरद्दकरदिया।यहतथ्यभीप्रकाशमेंआयाकिअगड़ेमुसलमानपिछड़ेवर्गकाप्रमाणपत्रलेकरनौकरियोंमेंजाबैठेहैं।यहांउन्हेंपिछड़ाकहलानेमेंकोईसंकोचनहींथा।यहीवहदौरथाजबदलितऔरपिछड़ेमुसलमानोंपरकामशुरूहुआथा।बैकवर्डमुस्लिममोर्चानामक

एकसंगठनसक्रियथा।नब्बेकेदशकमेंउभरेमंडलआंदोलनकाअसरपिछड़ेमुसलमानोंपरथा,यहसंगठनउसीको

लेकर चल रहा था। लेकिन इस संगठन ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिये नौकरियों में घुसपैठ और ऊँची जातियों के पिछड़े वर्गों में शामिल होने पर मौन धारण कर लिया था।

दलित मुसलमानों के बारे में नये चिंतन की शुरुआत हुई। उपेक्षित जनसमुदायों के बारे में नयी सोच विकसित हुई और एक नये संगठन पसमांदा मुस्लिम समाज का जन्म हुआ। 25 अक्टूबर 1998 को यह संगठन अस्तित्व में आया। इसने अति पिछड़े हिन्दुओं को भी साथ लेकर 13 दिसम्बर को उसी साल आरक्षण बचाओ रैली की। एक अध्ययन के क्रम का विस्तार जनसंगठन के रूप में हो जाना अपने आप में नयी बात है। मुस्लिम धोबी, नटबक्खो, पंवरिया, हलालखोर, भठियारा, गदहेड़ी, लालबेगी, पासी, डफाली, नालबंद आदि मुस्लिम पेशेवर जातियाँ हिन्दू दलितों की तरह ही हैं, लेकिन उन्हें हिन्दू दलितों की तरह ही सुविधा नहीं मिलती। पसमांदा मुस्लिम समाज ने इन उपेक्षित मुस्लिम आबादी को अपना एजेंडा बनाया। इसमें शक की कोई गुंजाईश नहीं कि हिन्दू जाति समुदायों की श्रेणियों की तरह ही मुस्लिम समुदायों में श्रेणियाँ विकसित हुई हैं, लेकिन उनका सशक्तीकरण नहीं हो सका है। राजनीति से लेकर सरकारी नौकरियों और शिक्षा दीक्षा में अगड़े समुदायों का एकाधिकार है। माना जा सकता है कि राजनीति में मुसलमानों की मध्य जाति समुदायों का कुछ असर दिखाई पड़ता है। हिन्दू अति पिछड़ी जाति समुदायों की तरह ही मोमिनो में कुछ राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ती है। हिन्दू अति पिछड़ी जाति समुदायों की तरह ही मोमिनो में भी कुछ राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे नीचे के दलित हाशिये से बाहर नजर आते हैं। राजनीति में इक्के दुक्के अंसारी, कुंजड़ा, मुकेरी, कुल्हैया, शेरशाहाबादी नेता दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उन समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर ही है। पिछले लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय की पार्टियों में मुस्लिम समाज से जीतने वाले नेताओं की संख्या छह से तीन हो गयी। कहा जाता है की यह मुसलमानों की नयी राजनीतिके ही कारण हुआ।

निष्कर्ष— बिहार में मुस्लिमों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दशा बहुत ही दयनीय रही है। मुस्लिम वर्तमान बिहार की आबादी का 16-87 प्रतिशत है (सन 2011 का आंकड़ा)। अविभाजित बिहार की जनसंख्या में ये 12-5 प्रतिशत थे। मुस्लिम राज्य के सबसे गरीब तबकों में से एक है। मुस्लिम आबादी 87 प्रतिशत गावों में रहती है। अधिकांश मुस्लिम परिवार खेतिहर-मजदूर के रूप में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। सही मायने में बिहार में मुस्लिमों का सामाजिक स्तर पर शोषण होता रहा है। विभिन्न दलों द्वारा साम्प्रदायिकता का हौवा खड़ा कर इनके वोट बैंक का इस्तेमाल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए करते आये हैं। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए बहुत ही कम कदम उठाये गए। मुस्लिमों को समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं मिला। मुस्लिमों के साथ हुए सामाजिक अन्याय के दोस्तर हैं दृढ़ पहला मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कि भांति ही जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उन्हें कम प्रतिनिधित्व मिला और ये पिछड़े हुए समूह बने रहे। दूसरा—मुस्लिमों को जो भी थोड़ा बहुत राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, उस पर ऊँची मुस्लिम (या अशराफ) ने कब्जा जमा लिया और पिछड़ी मुस्लिम जातियों (या अजलाफ) को बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला। जबकि इनकी आबादी 85 प्रतिशत तक मानी जाती है। राजनीतिक क्षेत्र की तरह ही आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण ऊँची मुस्लिम जातियों को ही जीवन के दूसरे क्षेत्र अर्थात् शिक्षा, नौकरी आदि में भी फायदा मिला।

सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह है की मंडलवादी राजनीति के नेतृत्वकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं वर्तमान नितीश कुमार के विगत 30 वर्षों के शासनकाल के सामाजिक न्याय के दौर में भी पिछड़े मुसलमानों को न्याय नहीं मिला है । नितीश कुमार की कैबिनेट में भी दो मुसलमान मंत्री बनाये गए –प्रवीण अमानुल्लाह और शाहिद अली खान जोकि अगड़े जाति से आते हैं, अलबत्ता सन् 1983–1985 में के कांग्रेस के शासनकाल में चंद्रशेखर सिंह के मुख्यमंत्री काल के दौरान पसमांदा मुसलमानों को अति पिछड़ों में शामिल किया गया था । यदि 1952–2000 तक के विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो कुल 275 मुसलमान उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीते, जिसमे 215 केवल अगड़े जाति के थे एवं वहीं पिछड़े जाति से मात्र 58 मुसलमान विधानसभा चुनाव जीते, जबकि इनका कुल प्रतिशत 85 मानी जाती है, जो कि अपने आप में कहीं से न्यायोचित नहीं है स उसी प्रकार यदि 1952–2009 लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो कुल 54 मुसलमान लोकसभा पहुंचे थे, जिसमे पिछड़ों की संख्या केवल 14 थी इससे साफ जाहिर होता है की अगड़े एवं पिछड़े मुसलमानों में हमेशा से ही गैर बराबरी रहा है जोकि कतई संतोषजनक नहीं है ।

भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का सवाल अब सतह पर है, यदि लोकतंत्र को पूरी आबादी तक ले जाना है तो ऐसे गैरबराबरी को नजरअंदाज नहीं करना होगा ।

संदर्भग्रंथसूची

1. प्रसाद, अनिरुद्ध, *सामाजिकन्यायएवंराजनीतिकसंतुलन*, रावतपब्लिकेशन, जयपुर 2002.
2. सिंह, आर० जी०, *भारतमेंसामाजिकपरिवर्तनएवंसामाजिकसमस्याएँ*, हिन्दीग्रंथअकादमी, मध्य प्रदेश, भोपाल– 1987.
3. सिन्हा, एस०पी०, *प्रोस्पेक्टिव आनसोशलजस्टिस*, कैपिटल, दिल्ली– 1991.
4. अली, अनवर, मसावात की जंग, पसेमंजर रू बिहार के पसमांदा मुसलमान. वाणी प्रकाशन, 2016
5. अहमद, डॉसज्जाद, *तहरीकआलइंडियामोमिनकॉन्फेस तारीखकेआईनेमें*, रांची, झारखण्ड ।
6. अहमद, इम्तियाज, कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटीफीकेशन एमॉंग मुस्लिम, मनोहर पब्लिकेशन, दिल्ली (सं.) 1973
7. चौधरी, प्रसन्न कुमार और श्रीकांत, " बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम (1912–1990)", वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.
8. नायक, *आनइक्वैलिटीएवंडिस्ट्रिक्ट्यूटिवजस्टिस*, इकोनॉमिकएण्डपोलिटिकल वीकली, नवम्बर–दिसम्बर 26, (11–12).
9. प्रसाद, ईश्वर, *रिजर्वेशन एक्शन फॉर सोशल इक्वालिटी*, विकास, दिल्ली, 1992.